the Rules applicable at that time. However, since 1-4-1990, the employees who opted for pension scheme were allowed the pensionary benefits. The scheme does not have the retrospective effect. As such there is no employee who retired prior to 1-4-1990 can be given pensionary benefits.

राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति

1635. **श्रीमती सरला माहेश्वरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांस्कृतिक नीति के प्रारूप पर संपूर्ण देश में चर्चा हुई थी और उनके मंत्रालय ने इस पर एक राष्ट्रीय बहस आरंभ की है, यदि हां, तो उनका मंत्रालय इस नीति के संबंध में किन निष्कर्षों पर पहुंचा है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय की इस संबंध में हुई संपूर्ण चर्चा को एक बृहद प्रकाशन के रूप में संकलित करने की कोई योजना है; और

(ग) क्या इस संपूर्ण चर्चा को ध्यान में रखते हुए उनके मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए सांस्कृतिक-नीति प्रारूप को अंतिम रूप दिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां। संसद ने माननीय सदस्यों के विचार जानने के लिए राष्ट्रीय संस्कृति नीति का प्रारूप संसद के दोनों सदनों के समापटल पर रख दिया गया है। सांस्कृतिक नीति के निष्कर्ष इन विचारों पर निर्भर होंगे।

(ख) और (ग) जी, हां।

हिन्दी तथा उर्दू विश्वविद्यालयों की स्थापना

1636. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दी तथा उर्दू विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां तो क्या इस संबंध में स्थान का चयन और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सरकार ने डा० शिव मंगल सिंह सुमन तथा श्री अज़ीज कुरैशी की अध्यक्षता में क्रमशः हिन्दी विश्वविद्यालय तथा उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में दो अलग-अलग समितियां गठित की थीं। इन दोनों समितियों ने सरकार को अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

इन रिपोर्टों की मंत्रालय में जांच की जा रही है लेकिन इन प्रस्तावित विश्वविद्यालयों के स्थान के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Legislation to Abolish Capitation Fee

1637. SHRIMATI VEENA VERMA :
SHRI SUSHILKUMAR
SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether in view of the latest Supreme court judgement with regard to revised fee structure for professional colleges, Government propose to bring before Parliament in comprehensive legislation to altogether abolish the capitation fee system in any form whatsoever; and

(b) if so, what steps have been/are being contemplated in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) and (b) As per the Supreme Court judgement of 4-2-1993 in Unni Krishnan's case, no professional college can charge any capitation fee over and above the permitted fee as prescribed by the competent authority in the State Government concerned. In order to implement the scheme with effect from 1993-94 itself the State Governments have taken suitable steps. In addition, the board uniform guidelines being finalised by the Central Government in respect of technical education will be given a statutory shape in the form of Regulations under the AICTE Act, 1987.

Steps to check copying in Examinations

1638. SHRI SOM PAL : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government has taken a note of mass copying phenomenon in examinations in schools and colleges and stringent actions taken by U. P. Government to prevent it;

(b) whether it is a fact that about 15000 students and 3000 teachers including 10 per cent PC girls were imprisoned in U. P. for mass copying in high schools; and

(c) if so, what steps the Central Government propose to take to stop copying by students that demoralise studious student community ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) to (c) The information